P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-3* (Part-1) November- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

कौशल विकास और उद्यमिता : आर्थिक विकास और रोजगार के वाहक

राम किशोर सागर
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामपुर (उ0प्र0)

सारांश

कौशल विकास एवं उद्यमिता का ज्ञान किसी भी देश के आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियॉ है। कौशल का उच्च स्तर और बेहतर मानक वाले देश घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रोजगार सम्बन्धी चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावशाली ढंग से समायोजित करते हैं। भारत की आजादी के 71 वर्ष बाद पहली बार कौशल को रोजगार परक बनाने की कोशिश की गयी जिसके परिणामस्वरूप कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन किया गया इससे भारत में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार किया जा सकेगा। गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद आदि भयंकर समस्याओं का निदान स्वतः ही इससे संभव हो सकेगा।

मुख्य शब्द : कौशल विकास एवं उद्यमिता।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर लाल किले की प्राचीन से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दस दामोदर भाई मोदी जी ने राष्ट्र से एक नवीन भारत बनाने का आहवान किया था। यह नया भारत सवा सौ करोड़ से अधिक भारतीयों के प्रयास से ही बन सकता हैं इसमें भी भारत के युवाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि युवा ही किसी राष्ट्र की वास्तविक ऊर्जा के स्रोत होते है। देश और समाज को नई दिशा देने का जज्बा केवल युवाओं में ही देखने को मिलता हैं इस सम्बन्ध में भारत अनेक देशों से धनी हैं हमारे देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की होने के कारण भारत युवाओं देश कहलाता है। वर्ष 2020 तक भारत की औसत आयु 29 वर्ष होगी जिसके परिणामस्वरुप हमारे देश में साढ़े चार करोड़ से भी अधिक जनसंख्या काम करने बाले आयुवर्ग का हिस्सा होगी इसी लिए कौशल विकास और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित कर युवाओ को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

कौशल विकास एवं ज्ञान किसी भी देश के आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं कौशल का उच्च स्तर और बेहतर मानक वाले देश घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रोजगार सम्बन्धी चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावशाली ढंग से समयोजित करते हैं भारत की आजादी के 71 वर्ष बाद पहली बार कौशल को रोजगार परक बनाने की कोशिश की गयी जिसके परिणाम स्वरूपकौशल विकास औरउद्यमशीलता मंत्रालय का गठन किया गया । इससे भारत में अधिक से अधिक युवाओ को रोजगार प्रदान किया जा सकेगा । गरीबी अशिक्षा, आतंकवाद आदि भयंकर समस्याओं का निदान स्वतः ही सम्भव हो सकेगा।

भारत की लगभग 75 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है यह ग्रामीण जनता अधिकतर कृषि आधारित व्यवसायों पर निर्भर है। असली भारत आज भी ग्रामीण परिवेश में कृषि और पशुपालन, मत्सय पालन, मधुमक्खी पालन पुष्पोत्पादन, बागबानी जैसे परम्परागत कार्यों में संलग्न है। ये गरीबी, अशिक्षा से संघर्ष करते हुए राष्ट्र के निर्माण में मानव संसाधन के रूप में योगदान कर रहे है। यदि दुनिया के साथ हमें प्रतिस्पर्धा करनी है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को मूलभूत सुविधाऐं प्रदान करके इनका सही मार्गदर्शन करना होगा। भारतीय युवाओं का सपना साकार करने के लिए ''कौशल भारत कुशल भारत'' योजना की शुरूआत विश्व कौशल दिवस 15 जुलाई 2015 को एक मिशन के रूप में की थी। इस मिशन के द्वारा 2022 तक बेरोजगार युवाओं को उनकी रूचि के अनुसार कौशल विकास करे रोजगार परक बनाना है।

कौशल विकास के क्षेत्र में हमारा देश अन्य देशों से काफी पीछे हैं नेशनल सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौशल विकास 3.5 प्रतिशत है। वर्ष 2019 तक भारत को 12 करोड़ कौशल युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी।

सरकार द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि देश के युवाओं को विविध प्रकार के कौशल विकास की शिक्षा के लिए कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना देश के प्रत्येक राज्य में की जायेंगी जिससे युवा वर्ग नौकरियो की तलाश की बजाये नौकरियां देने की मानसिकता का विकास कर सकेंगें। समावेशी विकास के लिए युवाओ में उद्यमशीलता की भावना का विकास अति आवयश्क है।

भारत में गरीबी दूर करके अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षित करके उन्हें रोजगार से जोड़ना है इसके अतिरिक्त इस मिशन का उद्देश्य विकास के नये क्षेत्रों को दूर कर उन्हें विकसित करने का प्रयास करना है। कौशल विकास योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैः–

1. वे गरीब बच्चे जो उचित शिक्षा प्राप्त करने में वंचित रह जाते हैं उनके अन्दर छुपे हुये कौशल की पहचान करना।
2. अधिक से अधिक युवा शक्ति के हुनर को पहचाना और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराना।
3. गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के अलावा गरीब परिवार के युवाओं में कौशल विकास प्रदान करके उन्हे आगे बढने का आत्मविश्वास जागृत करना।
4. युवाओं को तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना।
5. बेरोजगार युवाओं को आत्म निर्भर रोजगार परक बनाकर राष्ट्र के विकास और मुख्य धारा में सम्मिलित करना।
6. कौशल विकास के साथ–साथ उद्यमिता और मूल सवंर्धन को बढावा देना।
7. तकनीकी संस्थाओं को विश्व में बदलती तकनीकी के अनुसार गतिशील बनाना।

स्टार्टअप इण्डिया, मुद्रा, स्टैंड अप इण्डिया, स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं से निचले पायदान पर कौशल से युक्त युवाओं के लिए भी बडे पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ऐसे सेक्टर जहां सरकार बडे पैमाने पर निवेश कर रही है और नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से निवेश को बढावा दे रही है अर्थात कृषि, अवसंरचना, आटोमोटिव, कपडा, चमडा आदि क्षेत्रों में श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले नये लोगो और मौजूदा कामगारों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत सरकार की मेकइन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया एवं स्टार्ट सिटीज जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाने के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है :–

1. चीन की आर्थिक विकास दर धीमी होना एक अच्छे अवसर की प्राप्ति है।
2. कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढाने का पर्याप्त अवसर।
3. कौशल पूंजी में भारत विश्व स्तर पर गुणवत्ता बनाये हुए है।
4. अच्छे रोजगार के अवसरो की प्राप्ति।
5. युवा शक्ति को आर्थिक विकास में योगदान के रूप में स्वीकार करना।
6. भारत को विश्व कौशल का हब बनाना।

भारत वर्ष में युवा शक्ति 15–29 वर्ष की आयु वर्ग की 27 प्रतिषत है जो कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक युवा है। हमारे देश में मानवीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इन संसाधनों के द्वारा युवाओं में कौशल विकास के बल पर विश्व स्तर पर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। हमारे देश में ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या लगातार बनी हुई है। इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगें और वे आत्म निर्भर बनकर देश के आर्थिक विकास में योगदान देंगें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का कथन है कि '' कौशल विकास योजना केवल जेब में पैसे भरने जैसा नहीं है, बल्कि गरीबों के जीवन में आत्म विश्वास भरना है।'' युवाओं में इसी आत्म विश्वास के बल पर आत्म निर्भरता और शक्तिशाली विकसित राष्ट्रों की कतार में भारत के खडे होने की पूरी संभावना है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, ''भारत में श्रमशील जनसंख्या वर्ष 2040 तक तेजी से बढेगी जिसके कारण भारत विकासशील से विकसित राष्ट्रों की कतार में खडा हो सकेगा।''

अध्ययन का उद्देश्य

कौशल विकास की सबसे अधिक आवश्यकता वर्तमान समय में ग्रामीण भारत को है क्योकि यहाँ युवाओ को आसानी से प्रशिक्षण की सुविधाए उपलब्ध नहीं हैं। इसी को द्रष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार ने कई प्रकार की नई पहल की हैं जैसे दीन दयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), आजीविका आदि। इन सभी योजनाओ का उद्देश्य भारत के ग्रामीण युवाओ को आधुनिक बाजार की आवश्यकता के हिसाब से प्रशिक्षित करना है जिससे वे सामाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सके।

भारत में युवाओ के अलावा दूसरा क्षेत्र महिला प्रशिक्षण का है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न अध्यानो से ज्ञात हुआ है कि यदि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओ की भागीदारी पुरुषो के समकक्ष हो जाये तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 27% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन यह भागीदारी कौशल प्रशिक्षण के अभाव में संभव नहीं हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना जैसे कार्यक्रम स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओ को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओ के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार प्राप्त करने की होती है। इसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रशिक्षणदाता केन्द्रों के लियें प्रशिक्षण देने के उपरान्त रोजगार मेला लगवाने का भी प्रावधान है। इससे हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश के करोड़ों युवाओ को रोजगार के अवसर मुहैया करने में महत्वपूर्ण भूमिका

अदा करेगी। इसका मूल चरित्र स्वतंत्र भारत के संस्कार पुरुष महात्मा गाँधी जी के अनुरूप है। महात्मा गाँधी जी ने प्रारम्भ से ही हुनरमंद होने की पुरजोर वकालत की थी।

दुनिया के सर्वाधिक मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत की मानव शक्ति (श्रम शक्ति) में प्रत्येक माह दस लाख श्रम शक्ति की वृद्धि हो रही है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभकान्त का कहना है कि, "भारत फिलहाल बड़ी जनांकिक संभावना के साथ तेजी से बाद रही अर्थ व्यवस्था है इस विशाल आबादी को उचित कौशल के जरिये उत्पादक कार्य बल में बदल जाये, तो इससे सकल घरेलु उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर में तेज होने का मार्ग प्रशस्त्र हो सकता है।" स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा, स्टैंडअप इंडिया, स्वच्छ भारत जैसी योजनाओ से निचले पायेदान पर कौशल से युक्त युवाओ के लिए भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे है ऐसे सेक्टर जहाँ सरकार बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है और नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से निवेश को बढ़ावा दे रही है अर्थात कृषि, अवसंरचना, ऑटोमोटिव, कपड़ा, चमड़ा, आदि क्षेत्रो में श्रम बाजार में प्रवेश करने बाले नए लोगो और मौजूदा कामगारों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे है। इसी आधार पर कौशल परिवेश के लिए दस बिन्दूवार रूप रेखा तैयार की गयी है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है:–

1. तीव्र गति से व्यापक विस्तार एवं प्रसार।
2. गुणवत्ता युक्त परिणाम पर बल।
3. मानक से जुड़कर कौशल का विकास करना।
4. सभी जाति वर्गों में कौशल का विकास पर बल।
5. विश्व में कहीं भी कार्य करने योग्य बनाने का प्रयास।
6. कौशल क्षेत्र के समस्त प्रयासों को समेटते हुए उनमें सामन्जस्य स्थापित करना।
7. कुशलता को महत्वाकांक्षा से जोड़ने की पहल।
8. उद्योग जगत से जुड़ाव पर बल।
9. शिक्षण एवं प्रशिक्षण के मध्य अर्न्तसम्बन्ध स्थापित करना।
10. तकनीकी के उपयोग पर बल।

कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या वर्ष 2014 में 1736 थी जो कि वर्ष 2017 में बढ़कर 8662 तक पहुँच गयी अर्थात 499 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि प्रशिक्षण की तुलना की जाये तो वर्ष 2014 में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 19,54,300 जो कि वर्ष 2017 में बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख 25 हजार हो गई। इस प्रकार कौशल विकास योजनाओं से युवाओं के प्रशिक्षण प्रयासों में तेजी आयी है।

सम्पोषित विकास के लिए युवा कौशल विकास

ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीब परिवारों के युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता के विकास पर बहुत बल दे रहा है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के कार्यान्वयन से राष्ट्र के सम्पोषित विकास के लिए इस राष्ट्रीय एजेण्डा पर बल दिया जा रहा है। आधुनिक बाजार में भारत के ग्रामीण निर्धनों को आगे लाने में बहुत सारी चुनौतियां है। उदाहरण स्वरूप– औपचारिक शिक्षा और बाजार के अनुकूल कौशल की कमी होना। विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, वित पोषण रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देने, रोजगार को स्थायी बनाने, अजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने जैसे उपायों के द्वारा यह योजना अन्तर को पाटने का कार्य करती है।

सम्पोषित विकास योजना की विशेषताऐं

1. ग्रामीण गरीबी को ग्राम आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. समावेशी कार्यक्रम तैयार करना।
3. सामाजिक स्तर पर वंचित समूहों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत महिलाएं 33 प्रतिशत) को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया।
4. प्रशिक्षण से लेकर अजीविका उन्नयन पर जोर देना।
5. नियोजन के बाद सहायता, प्रवास सहायता और पूर्व छात्र नेटवर्क तैयार करना।
6. रोजगार साझेदारी तैयार करने की दिशा में सकारात्मक पहल।
7. प्रशिक्षित 75 प्रतिशत युवाओं को रोजगार की गारण्टी।
8. जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं वामंपी उग्रवादी से प्रभावित 27 जिलों में निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं का शुभारम्भ करना।

अनेक मंत्रालयों की प्रमुख योजनाएं

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग स्कमी, क्राफ्टमेन ट्रेनिंग स्कीम, कौशल विकास प्रयास आदि।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान।

कपड़ा मंत्रालय

इंटीग्रेटिड कौशल विकास नीति

कृषि मंत्रालय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि चिकित्सालय एवं कृषि व्यापार केन्द्र स्कीम कृषि सुधार क्षेत्र का सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग मंत्रालय– उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता स्कीम, स्किल अपग्रेडेशन एवं क्वालिटी इम्पूवमेन्ट एवं वुमेन कोर प्लान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अप्रेन्टिसशिप स्कीम, वोकेशललाइजेशन ऑफ स्कूल एजूकेशन, समुदाय विकास कार्यक्रम

सूचना एवं संचार विकास मंत्रालय

स्टेट फॉर स्किल डबलमेंट, इन इलैक्ट्रानिक सिस्टम डबलमेंट इन ई.एस0डी. एम. फॉर डिजिटल इण्डिया।

कौशल भारत कुशल भारत मिशन के अन्तर्गत हमारी केन्द्र सरकार ने गरीब युवाओं प्रशिक्षित करके बेरोजगारी की समस्या और गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के द्वारा युवाओं मे आत्मविश्वास पैदाकर उनकी उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ शिक्षण संस्थाएं मिलकर कार्य करेगी भारत में कौशल

विकास मिशन सरकार महत्वपूर्ण परियोजना है। इस योजना से राष्ट्र का निर्माण व्यवस्थित रूप से किया जा सकेगा भारतवर्ष में युवाशक्ति दुनिया के अन्य देशों की तुलना सर्वाधिक है। हमारे देश में मानवीय संसाधन पर्याप्त मात्र में उपलब्ध है। इन संसाधनों के द्वारा युवाओं में कौशल विकास के बल पर विश्व–स्तर पर भारत का एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। हमारे देश में ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार एवं गरीबी की समस्या लगातार बनी हुई है। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेंगे और आत्म निर्भर बन सकते है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का कथन है ''कौशल विकास योजना'' केवल जेब में पैसे भरने जैसा नहीं है, बल्कि गरीबों के जीवन में आत्मविश्वास भरना है'' युवाओं में इसी आत्मविश्वास के बल पर आत्मनिर्भरता और शक्तिशाली विकसित राष्ट्रों की कतार में भारत खडा होगा।

निष्कर्ष

भारत में युवाओ को प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बना देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि हमें उनकी सामर्थ्य बढ़ाने की ओर इस प्रकार कार्य करना होगा जिससे की वे रोजगार तलाशने के बजाये रोजगार देने वाले बन सके। केंद्र सरकार की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर देने के साथ–साथ स्वावलंबन हेतु आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम 'संकल्प' की शुरुआत की गयी है। इसके अंतरगत लगभग 3 करोड़ 50 लाख युवाओ को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्रीय वित्तीय प्रावधान के अंतर्गत स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम 'स्ट्राइव' के अगले चरण पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 2200 करोड़ रुपये व्यय करने का की योजना है।

हमारे देश के युवाओ को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने और रोजगार प्रदाता बनाने के लिए उनमे उद्यमिता का भाब पैदा करना नितांत आवयश्क है। यहाँ स्टेंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों का महत्व सामने आता है। इनके अलावा 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया जैसी पहल भी हैं जिनके द्वारा भारत वैश्विक बाजार में स्वयं को एक ब्रांड के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हमे इस तथ्य को भी सहर्ष स्वीकार करना होगा कि हमारे पास स्किल, रि–स्किल और अप–स्किल अपनाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपनाकर ही हम विश्व में नवाचार के साथ अपने आप को खड़ा कर सकते है और एक नवीन भारत के निर्माण का सपना भी साकार कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *मोदी, अनीता, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बढ़ते अवसर, कुरूक्षेत्र फरवरी 2013 पृ0 सं0 2017–18*
2. *योजना उद्यमिता शिक्षा पर प्रमुख योजना सूचना भवन नई दिल्ली दिसम्बर 2016 पृ0सं0–2*
3. *दाधीच, बालेन्दु शर्मा, रफ्तार पकड़ रहा है डिजिटल आधारभूत ढांचे का विकास, 'कुरुक्षेत्र' दिसम्बर 2016 पृं0 सं0–31*
4. *सिंह, जतिंदर, कौशल विकास व युवा शक्तिकरण 'योजना' मई 2017 पृं0सं0*
5. *नायडू एम. वेंकैया गाथा नये भारत की योजना मई 2017 पृ0सं0–11*
6. *राय, ओंकार सशक्त डिजिटल समाज बनता भारत 'योजना' मई 2017 पृ0सं0–30*
7. *प्रसाद श्याम सुन्दर, सशक्त युवा के लिए समन्वित नीतिया जरूरी 'योजना' जून 2017 पृ0सं0–43*
8. *कुमार संजीव समावेशी विकास के लिए जरूरी है कौशल विकास 'कुरूक्षेत्र' सितम्बर 2017 पृ0सं0–35–36*
9. *सागर, आर. के. भारत के आर्थिक विकास में कौशल विकास एवं उद्यमिता की भूमिका, Creating A Unified for the sustainable development "education and empowerment", govt raza p.g college Rampur (U.P),27-28 january 2018, पृं0 सं0–423-427*
10. *अमिताभकान्त, नवाचार और उद्यमिता रोजगार की कुंजी, "योजना" सितम्बर 2018 पृं0 सं0–*19-21
11. *इण्टरनेट*
12. *विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्रिकाऐं।*